

डेयरी क्षेत्र और मुक्त व्यापार का वरिध

प्रलिस के लयि:

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP), श्वेत क्रांति

मेन्स के लयि:

भारत का डेयरी क्षेत्र RCEP का वरिध, महत्त्व, चुनौतियाँ, डेयरी क्षेत्र से संबंधित समाधान ।

चर्चा में क्यों?

कुछ विशिषज्ञों के अनुसार, [क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी \(Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP\)](#) से भारत का हटना कसिसन संगठनों, ट्रेड यूनियनों, छोटे और मध्यम औद्योगिक उत्पादकों के संघों के लयि एक बड़ी जीत है ।

- इसी तरह का वचिर भारतीय डेयरी क्षेत्र द्वारा भी व्यक्त कयि जाता है, जनिहोंने डेयरी उत्पादों में मुक्त व्यापार का वरिध कयि था ।

RCEP विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉकों में से एक है, जसि पर 15 देशों (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसियान के 10 देशों का समूह) के बीच हस्ताक्षर कयि गए हैं । वर्ष 2020 में भारत RCEP वार्ता से हट गया है ।

प्रमुख बदि

भारत के डेयरी क्षेत्र द्वारा RCEP का वरिध:

- ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे वैश्विक दुग्ध उत्पादक देश RCEP समझौते में शामिल हैं ।
- पछिले 25 वर्षों में, भारतीय नीति ने जानबूझकर नजि दुध कंपनियों के विकास को प्रोत्साहित कयि है । फलिहाल ये कंपनियाँ भारतीय कसिसानों से दुध खरीदने को बाध्य हैं ।
 - कारण यह है कि भारत में वदिशी डेयरी उत्पादों पर लागू टैरिफि लगभग 35% है ।
 - यदि भारत ने RCEP पर हस्ताक्षर कयि होते तो बाध्य शुल्क शून्य हो जाता ।
- तब भारतीय कसिसानों से दुध खरीदने के बजाय न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया से दुध आयात करना कहीं अधिक लाभदायक होता । इसलिये भारत समझौते के वरिध में था ।
- इसके अलावा नकिट भवषिय में ऐसा कोई नहीं है जो भारत दुध से वंचित होगा । नीतिआयोग के अनुसार, भारत के वर्ष 2033 तक दुग्ध-अधिशिष देश होने की संभावना है ।

नोट:

- [विश्व व्यापार संगठन \(WTO\)](#) एक देश को एक नशिचति सीमा तक अधिकतम टैरिफि या कसिी दयि गए कमोडिटी लाइन के लयि बाध्य टैरिफि तय करने की अनुमति देता है ।
 - दूसरी ओर RCEP देशों को अगले 15 वर्षों के भीतर उस स्तर को शून्य करने के लयि बाध्य करता है ।
 - कसिी उत्पाद श्रेणी में अधिकतम टैरिफि को बाध्य टैरिफि दर कहा जाता है ।
 - हालाँकि टैरिफि दरें सभी उत्पादों और देशों में भनिन हैं । वास्तविक टैरिफि दर को लागू टैरिफि दर कहा जाता है ।

श्वेत क्रांति(1970):

- भारत में श्वेत क्रांति की अवधारणा '[डॉ. वरगीज कुरयिन](#)' द्वारा प्रस्तुत की गई थी ।

- उनके अधीन गुजरात सहकारी दुग्ध वपिणन संघ लिमिटेड और [राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड](#) (NDDB) जैसे कई महत्त्वपूर्ण संस्थान स्थापित किये गए थे।
- ग्राम दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियों को इस क्रांति की आधारशिला माना जाता है। 'ऑपरेशन फ्लड' के दौरान उनकी प्रमुख भूमिका को विकास के इंजन के रूप में देखा जाता है।
- नीति ने संयुक्त उद्यमों: वलिय और अधिग्रहण के माध्यम से भारतीय डेयरी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय डेयरी नगियों के प्रवेश का भी समर्थन किया है।

भारतीय डेयरी क्षेत्र

■ डेयरी क्षेत्र का महत्त्व:

- **श्रम गहन क्षेत्र:** खेत पर नरिभर आबादी में जैसे किसान और खेतहिर मजदूर भी शामिल हैं जो डेयरी एवं पशुधन पर नरिभर हैं। इनकी संख्या लगभग 70 मिलियन है।
 - इसके अलावा मवेशी और भैंस पालन में कुल कार्यबल 7.7 मिलियन में 69 प्रतिशत महिला श्रमिक हैं।
- **अर्थव्यवस्था में योगदान:** कृषि से [सकल मूल्य वृद्धि](#) (GVA) में पशुधन क्षेत्र का योगदान 2019-20 में 28 प्रतिशत था।
 - दुग्ध उत्पादन में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि दर से किसानों को सूखे और बाढ़ के दौरान एक बड़ा आर्थिक सहारा प्राप्त होता है।
- **आपदा के समय किसानों की मदद करना:** प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने पर दूध का उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि किसान तब पशुपालन पर अधिक नरिभर होते हैं।

○ संबद्ध मुद्दे

- **अदृश्य श्रम:** किसान प्रायः पाँच में से दो दुधारू पशु आजीविका के लिये रखते हैं। ऐसे में परिवार के उपयोग हेतु दुग्ध उत्पादन के लिये आवश्यक श्रम परिवार की अवैतनिक या औपचारिक रूप से बेरोजगार महिलाओं के हिससे आता है।
 - उनमें से भूमिहीन और सीमांत किसानों के पास दूध के लिये खरीदारों की कमी होने पर आजीविका का कोई विकल्प नहीं है।
- **डेयरी क्षेत्र की असंगति प्रकृति:** गन्ना, गेहूँ और चावल उत्पादक किसानों के विपरीत पशुपालक असंगति हैं और उनके पास अपने अधिकारों की वकालत करने के लिये राजनीतिक ताकत नहीं है।
- **अलाभकारी मूल्य निर्धारण:** हालाँकि उत्पादित दूध का मूल्य भारत में गेहूँ और चावल के उत्पादन के संयुक्त मूल्य से अधिक है लेकिन उत्पादन की लागत और दूध के लिये [न्यूनतम समर्थन मूल्य](#) का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है।
- **अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव:** भले ही डेयरी सहकारी समितियाँ देश में दूध के कुल वपिणन योग्य अधिशेष का लगभग 40% संभालती हैं, लेकिन वे भूमिहीन या छोटे किसानों का पसंदीदा विकल्प नहीं हैं।
 - ऐसा इसलिए है क्योंकि डेयरी सहकारी समितियों द्वारा खरीदा गया 75% से अधिक दूध अपनी कम मूल्य सीमा पर है।

डेयरी क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल:

- [डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2022](#): यह दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास करता है।
- [राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम](#): इसे देश में पशुओं के बीच पैर और मुँह की बीमारी (FMD) और ब्रुसेल्लोसिस को नियंत्रित करने और मटाने के लिये शुरू किया गया था।
- **पशु-आधार:** यह जानवरों का पता लगाने की क्षमता के लिये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक अद्वितीय आईडी है।
- [राष्ट्रीय गोकुल मिशन](#): इसे वर्ष 2019 में एकीकृत मवेशी विकास केंद्रों के रूप में 21 गोकुल ग्राम स्थापित करने के लिये लॉन्च किया गया था।

आगे की राह

- **उत्पादकता में वृद्धि:** पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन सुविधाएँ और डेयरी पशुओं का प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके तथा इससे दूध उत्पादन की लागत कम हो सकती है।
 - साथ ही पशु चिकित्सा सेवाओं, कृत्रिम गर्भाधान (एआई), चारा और किसान शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करके दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
 - सरकार और डेयरी उद्योग इस दशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
- **उत्पादन, प्रसंस्करण और वपिणन बुनियादी ढाँचे में वृद्धि:** भारत के लिये एक डेयरी नरियातक देश के रूप में उभरने के लिये:
 - उच्च उत्पादन, प्रसंस्करण और वपिणन बुनियादी ढाँचे को विकसित करना अनिवार्य है जो अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो।
 - इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे और बजिली की कमी को दूर करने के लिये सौर ऊर्जा संचालित डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश करने की आवश्यकता है।
 - साथ ही डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करने की जरूरत है। इस प्रयास में सरकार को [किसान उत्पादक संगठनों](#) को बढ़ावा देना चाहिये।

<https://www.youtube.com/watch?v=ShKBAHNW8kM>

स्रोत: द हट्टू

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/dairy-sector-opposition-to-free-trade>

